कांग्रेस के मिशन रिपीट के खतरे से डरी भाजपा ने धूमल को घोषित किया

शिमला/शैल। कांग्रेस जो दो महीने कहीं भी मुकाबले में नहीं थी वो मुकाबले में आ गई व मिशन रिपीट का डंका पीट दिया। हालांकि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं की कोई बडी रैलियां प्रदेश में नहीं हुई। बावजूद इसके अकेले वीरभद्र सिंह के दम पर कांग्रेस ने ये जलवा दिखा दिया।

मोदी व शाह की जोड़ी ने प्रदेश में आरएसएस से लेकर, साइबर आर्मी तक सब मैदान में उतार दिए लेकिन कोई असर नजर नहीं आया। मोदी – शाह के लाडले जगत प्रकाश नड्डा भी हाथ पांव मारते रहे लेकिन रिपोर्ट नेगेटिव ही रही। भाजपा की आक्रमकता का प्रदेश की जनता पर ज्यादा असर नहीं है।

कांग्रेस के रिपीट मिशन को बढ़ता देख व भाजपा के एक बड़े तबके के खामोश हो जाने से डरी भाजपा ने पार्टी में नई जान फूंकने के लिए आखिर में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने राजगढ़ की रैली पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री घोषित कर दिया है।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने राजगढ़ में आयोजित एक जनसभा में ये बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अभी धूमल पूर्व मुख्यमंत्री हैं व वो 18 दिसंबर के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। इस ऐलान का प्रदेश भाजपा को निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। इस एलान के बाद मोदी सरकार में मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और धूमल खेमों में चली खींचतान पर विराम लग गया है। प्रदेश में एक बार फिर धूमल खेमा हावी हो गया है। अमित शाह के इस ऐलान के बाद जगत प्रकाश नड्डा के मुख्यमंत्री बनने का सपना फिलहाल खत्म हो गया है और जैसे कांग्रेस पर वीरभद्र सिंह व उनके परिवार का वर्चस्व है उसी तरह अब भाजपा पर भी धूमल परिवार के वर्चस्व होने का रास्ता साफ हो गया है।

भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जोड़ी को हिमाचल प्रदेश भाजपा से चाहे वो टिकटों का बंटवारा हो या अब मुख्यमंत्री का चेहरा उतारने का मामला हो, कड़ी चुनौती मिली है। यह पहली बार है कि 2014 के बाद बाकियों राज्यों की अपेक्षा हिमाचल भाजपा ने अपनी बात राष्ट्रीय नेतृत्व से मनवाई है।

इससे पहले टिकट बंटवारे को लेकर भाजपा आलाकमान तीन दिन तक टिकटों का एलान नहीं कर पाया था। आखिर में जब टिकटों का एलान हुआ तो चंद सीटों को छोड़कर हिमाचल के नेताओं की सिफारिशों को दरकिनार नहीं किया जा सका था।

क्रप्शन के मामले में भाजपा के 19 लोग जमानत पर:मनप्रीत सिंह बादल

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसएिशन को जमीन आवंटन के मामले में मचाई धांधलियों पर पंजाब के वित मंत्री व कांग्रेस नेता मनप्रीत सिंह बादल ने भाजपा नेता प्रेम कुमार धूमल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों को घेर लिया है। एचपीसीए की धांधलियों को लेकर विजीलेंस की ओर से धर्मशाला की अदालत में दायर चालान को जारी करते हुए बादल ने कहा कि प्रदेश में भाजपा की चुनावी रैलियों में मोदी हल्ला बोलते आ रहे हैं कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह व प्रदेश सरकार जमानत पर है। लेकिन वो ये बताना भूल जाते हैं जिन प्रेम कुमार धूमल को उन्होंने सी एम प्रत्याशी घोषित किया है, क्या वो जमानत पर नहीं है। उनके पुत्र, भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर क्या बेल पर नहीं है।

धूमल, अनुराग समेत 19 लोग जमानत पर हैं। उनके खिलाफ अदालत में चालान दायर हुआ है और अदालत ने संज्ञान लिया हुआ है। बादल राजधानी में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बोल रहे थे।

बादल ने प्रधानमंत्री मोदी से सवाल किया कि क्या वो धूमल का नाम जो सीएम प्रत्याशी के तौर पर घोषित किया है, उसे वापस लेंगे। चूंकि वो जमानत पर है तो क्या वो धूमल का टिकट वापस लेंगे। इस मौके पर हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन मामले में धूमल, उनके बेटे भाजपा सांसद अनुराग व बाकियों के खिलाफ दायर चालान की प्रति भी मीडिया को जारी की। चालान में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल आरोपी नंबर 13 हैं व उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) लगी हुई हैं। जबकि उनके पुत्र व भाजपा सांसद जो एचपीसीए के अध्यक्ष थे, को आरोपी नंबर एक बनाया गया है। जबकि धूमल के छोटे पुत्र अरुण धूमल को आरोपी नंबर आठ बनाया गया है। विजीलेंस ने इन सबके खिलाफ 1 अगस्त 2013 को एफआईआर नंबर 12/13 के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 406, 120 बी और भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 13(2)के तहत मामला दर्ज किया था।

चालान के अलावा बादल ने धूमल व बाकियों की ओर से स्पेशल जज कांगड़ा की अदालत में 27 अक्तूबर 2014 को लगाई जमानत अर्जी भी मीडिया को जारी की। अदालत ने उनकी ये अर्जी मंजूर कर ली थी।

बादल ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के बेटे जय शाह की संपति एक साल में 16 हजार गुणा बड़ जाने पर भी सवाल उठाया व कहा कि इस मामले की कोई जांच नहीं हो रही है।

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार सीबीआई और इडी जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल केवल गैर भाजपा पार्टियों के नेताओ के खिलाफ कर रही है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के घर तो उस दिन सीबीआई छापेमारी हुई जिस दिन उनकी बेटी का ब्याह था। उन्होंने कहा कि ये हिमाचल की जनता नौ नवंबर को इसका जवाब देगी।

पंजाब से हिमाचल के हिस्से को लेकर पूछे सवाल के जवाब में बादल ने कहा कि हिमाचल व पंजाब एक जड़ दो तने हैं। पंजाब हिमाचल की हिस्सेदारी देने के लिए रजामंद हैं। जो भी मसले उठेंगे उन्हें हल किया जाएगा। उन्होंने कहा 2014 के लोकसभा चुनावों में मोदी ने प्रदेश में कई जलसे किए व दर्जनों वादे किए लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया। अगर भाजपा ने एक भी वादा पूरा किया है तो वो हिमाचल के मतदाताओं के मतों के हकदार बन जाते हैं।

उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता कश्मीर को लेकर सवाल उठाते हैं। उन्हें शायद नहीं पता कि पंजाब के गुरदासपुर जिले में पाकिस्तान ने डीसी बिठा दिया था। फाजिल्का तहसील पंजाब में चली गई थी। लेकिन पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू न होते व उनका रसूख न होता तो ये इलाके आज पाकिस्तान में होते। कश्मीर जो आज हिंदुस्तान में हैं तो ये नेहरू व कांग्रेस की वजह से हैं।

भाजपा का काम केवल बंटवारे की राजनीति करना हैं। इसके अलावा उसके पास कोई काम नहीं है।

हिमाचल विधानसभा चुनावों में हैं 50 लाख 25 हजार 945 मतदाता:राजपूत

शिमला/शैल। बालीवुड की मशहूर व चर्चित अदाकारा कंगना रणौत, प्रीति जिंटा, गायक मोहित चौहान के अलावा दुनिया में डब्ल्यू डब्ल्यू एफ रेसलिंग के बादशाह द ग्रेट खली ने हिमाचल प्रदेश चुनाव विभाग के आग्रह पर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों में जनता से अपना मत डालने की अपील बिल्कुल फ्री की है।

प्रदेश चुनाव विभाग की ओर से तैयार की गई ये अपीलें चैनलों में छाई हुई हैं। इसके अलावा हिमाचल की एक दृष्टिहीन छात्रा मुस्कान भी जनता से 9 नवंबर को मतदान करने की अपील कर रही हैं।

प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी पुष्पेंद्र राजपूत ने कहा कि विभाग ने हिमाचल के सभी विख्यात शख्सियतों से मतदान के लिए अपील करने का आग्रह किया था। जिसमें से प्रमुखतय: कंगणा रणौत, प्रीति जिंटा, मोहित चौहान और ग्रेट खली ने उनके आग्रह को मंजूर कर लिया।

याद रहे कि प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग ने कंगणा रणौत से विभाग का एक विज्ञापन करने का आग्रह किया था। लेकिन कंगणा ने सरकार का ये आग्रह ठुकरा दिया था पर चुनाव विभाग के आग्रह को उन्होंने मंजूर कर लिया।

राजपूत हिमाचल में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर चुनाव विभाग की ओर से की गई तैयारियों का ब्योरा मीडिया के समक्ष पेश कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने इस बावत मीडिया को एक वीडियों भी दिखाया।

उन्होंने कहा कि इस बार इन चुनावों में 50 लाख 25 हजार 945 मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे। इनमें से 25 लाख 31 हजार 521 पुरुष और 24 लाख 57 हजार 32 मत महिलाओं के हैं। सर्विस मतदाता 37 हजार 574 हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 24 ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जहां मतदाताओं को पांच किलोमीटर दूर से अपना मत डालने जाना पड़ेगा। यहां के लिए चुनाव विभाग ने खास इंतजाम किए हैं।

चुनाव कराने के लिए 37 हजार 605 कर्मियों का तैनाती की गई हैं। जबकि कानून व्यवस्था चाक चौबंद रखने के लिए 11 हजार से ज्यादा प्रदेश पुलिस के कर्मी छह हजार से ज्यादा होमगार्ड और 75 कंपनियां केंद्रीय बलों की तैनात की जानी हैं। अभी तक 65 कंपनियों की तैनाती को मंजूरी मिल गई हैं, दस और कंपनियां मांगी गई हैं।

इस मौके पर एडीजीपी कानून व्यवस्था अतुल वर्मा ने कहा कि पुलिस, आबकारी विभाग व आयकर विभाग ने अभी तक विभिन्न स्थानों पर एक करोड़ 12 लाख की नकदी व 65 हजार लीटर शराब बरामद की हैं। इसके अलावा तीन किलो सोना भी बरामद किया हैं। लोगों ने करीब 87 हजार हथियारों में से 74 हजार के करीब हथियार विभिन्न थानों में जमा करा दिए हैं।

जनता में झूठ बोलना कांग्रेस की पुरानी आदत:धूमल

शिमला/शैल। प्रेम कुमार धूमल ने कांग्रेस के 32 पेज के घोषणा पत्र में किए गए वादों के साथ ही उसकी ईमानदारी पर भी सवाल खड़े किए।

कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सवाल खड़े करते हुए प्रेम कुमार धूमल ने कहा कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र के माध्यम से तमाम आधारहीन वादे किए हैं। हालांकि शायद उन्हें यह पता नहीं है कि इन प्रस्तावित वादों में से अधिकांश को कांग्रेस ने अपने बीते 5 साल के कार्यकाल के दौरान पूरा नहीं किया गया। 50 प्रतिशत चुनावी वादे पूरा नहीं करने के बावजूद कांग्रेस ने घोषणा पत्र को व्यापक बनाने के लिए फिर उन्हीं बिंदुओं को उठाया है।

धूमल ने कहा 'जनता की तरफ से मैं कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र बनाने वालों को याद दिलाना चाहूंगा कि चुनावी घोषणा पत्र के 275 बिंदुओं में 50 प्रतिशत से ज्यादा को 2012 के घोषणा पत्र में से ही कॉपी किया गया है। उन्होंने अपने पिछले घोषणा पत्र में जन शिकायत आयुक्त की नियुक्ति कर्मचारियों को 4 – 9 – 14 लाभ देने, 65, 70 और 75 साल की उम्र पूरी करने पर पेंशनर्स को 5 – 10 – 15 का लाभ देना, शिमला – हमीरपुर – पठानकोट से 4 राष्ट्रीय राजमार्गो को पूरा करना आदि का वादा किया था। अब वे उन्हीं को दोहरा रहे हैं। लेकिन जनता उन पर भरोसा कैसे कर सकती है जब उन्होंने बीते 5 साल के दौरान इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। हिमाचल प्रदेश के लिए जीएसटी की एग्जम्प्शन (छूट) सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख करने के मुद्दे पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यह स्पष्ट कर दिया है कि राज्य सरकार ने खुद ही यह सीमा स्वीकार की है। उन्होंने 20 लाख की मांग की होती तो इसे भी पहले ही 20 लाख कर दिया होता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ भाजपा के विजन डॉक्युमेंट की नकल की है।

उन्होंने कहा कृषि और उद्यानिकी के मसले पर कांग्रेस ने पिछले घोषणा पत्र में वादा किया था कि वे कृषि मूल्य तय करने के लिए एक कृषि आयुक्त की नियुक्ति करेंगे। लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। इसी प्रकार उन्होंने जनता के समक्ष खुलासा किए बिना कर्ज सहायता देने का वादा किया था।

उन्होंने कहा कर्मचारियों को अपने महंगाई भत्ते की बकाया किस्त के लिए 10 महीने का इंतजार करना पड़ा और एचआरटीसी, कृषि और उद्यानिकी विश्वविद्यालयों के पेंशनरों को अपनी पेंशन के लिए कई महीनों का इंतजार करना पड़ा।

हिमाचल में 338 में से 158 करोड़पति, 92 आपराधिक छवि वाले उम्मीदवार लड़ रहे चुनाव

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिर्फोम्स ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 में चुनाव लड़ने वाले सभी 338 उम्मीदवारों के शपथ पत्रों का विश्लेषण किया।

जिसमें 338 में से 61 उम्मीदवारों ने अपने ऊपर आपराधिक मामले घोषित किये हैं। 31 उम्मीदवारों ने अपने ऊपर गंभीर आपराधिक मामले घोषित किये हैं। निर्वाचन क्षेत्र दून से INC के उम्मीदवार ने अपने ऊपर हत्या (आई पी सी 302) से सम्बन्धित मामला घोषित किया है। 2 उम्मीदवारों ने अपने ऊपर हत्या का प्रयास (आई पी सी 307) से सम्बन्धित मामले घोषित किये है।

INC के 68 में से 6, BJP के 68 में से 23 , BSP के 42 में से 3, CPI(M) के 14 में से 10 , 112 में से 16 निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपने ऊपर आपराधिक मामलें घोषित किये हैं।

INC के 68 में से 3, BJP के 68 में से 9, BSP के 42 में से 2, CPI(M) के 14 में से 9, 112 में से 6 निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपने ऊपर गंभीर आपराधिक मामलें घोषित किये हैं जिनमें हत्या, हत्या का प्रयास, और अपहरण जैसे मामले शामिल है।

हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 में 2 निर्वाचन क्षेत्र डलहौज़ी और मंडी ऐसे हैं जहाँ राजनीतिक दलों के 3 और 3 से अधिक उम्मीदवारों ने अपने ऊपर आपराधिक मामले घोषित किये हैं।

हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 में 338 में से 158 करोड़पति उम्मीदवार हैं। जिनमें INC के 68 में से 59, BJP के 68 में से 47, BSP के 42 में से 6 , CPI(M) के 14 में से 3 , CPI के 3 में से 1 और 112 में से 36 उम्मीदवार करोड़पति हैं। इनकी घोषित संपत्ति 1 करोड़ से ज़्यादा है।

मतदाताओं की खामोशी कहीं त्रिशंकु का संकेत तो नही

इस चुनाव में धूमल और वीरभद्र की प्रतिष्ठा दांव पर

एक विश्लेषण

शिमला/शैल। प्रदेश में अगली सरकार किसकी बनेगी इसके लिये नौ तारीख को मतदान होगा। दोनो बड़े दल भाजपा और कांग्रेस सरकार बनाने के दावे कर रहे हैं। भाजपा तो 50 प्लस सीटे जीतने का दावा कर रही है लेकिन इन दावों के वाबजूद मतदाता अभी तक मौन चल रहा है। वह खुलकर किसी के पक्ष में नही आ रहा है। भाजपा ने जब बूथ स्तर के त्रिदेव और फिर विभिन्न प्रकोष्ठों द्वारा आयोजित सम्मलेनो का आयोजन किया था उस समय भाजपा के पक्ष में एक बड़ा माहौल खड़ा हो गया था। लेकिन इस माहौल को पहली बार धक्का उस समय लगा था जब नगर निगम शिमला के चुनाव में भाजपा को स्पष्ट बहुमत नही मिल पायां निर्दलीयों को लेकर सत्ता में आये। और यह स्थिति तब हुई जब इस चुनाव से पहले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी शिमला

के रिज मैदान पर एक जनसभा को संबोधित कर गये थे। नगर निगम शिमला के चुनाव की हार इस बात का संकेत था कि अब अकेले केन्द्र सरकार के भरोसे को केन्द्रिय नेताओं की छवि के सहारे ही प्रदेश में चुनावी सफलता नही पायी जा सकती है।

हिमाचल की राजनीतिक संस्कृति देश के अन्य राज्यों से भिन्न है। यहां पर बिजली, पानी सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाएं लगभग पुरे प्रदेश में उपलब्ध हैं। बल्कि कई स्कूल तो प्रदेश उच्च न्यायालय के युक्तिकरण के आदेशों के तहत बन्द करने पड़े हैं। प्रदेश में यह मांग कम है कि नये संस्थान खोले जायें वरन् यह है कि जो खोले गये हैं वह सुचारू रूप से चलें। इन संस्थानों में पूरा स्टॉफ उपलब्ध हो। हर स्कूल, कालिज में पर्याप्त अध्यापक हों और किसी भी अस्पताल में डाक्टरों की कमी न हों। सरकारी कार्यालयों में समुचित कर्मचारी तैनात हों। प्रदेश के हर क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या ही यह है कि वहा खुले संस्थान/कार्यालय में स्टॉफ की कमी रहती है। लेकिन यह कमी तो नयी भर्तियों के माध्यम से ही पूरी की जा सकती है। परन्तु यह भर्तियां करने के लिये सरकार के पास धन की कमी आड़े आती है। इसके लिये कान्ट्रैक्ट और आऊटसोर्स जैसे तरीके अपनाये जाते हैं और उनमें मैरिट की जगह भाई-भतीजा बाद चलता है। आगे चलकर ऐसे भर्ती हुए लोगों को नियमित किये जाने की मांग उठती है जिसे मौजदा आरएण्डपी रूल्ज़ के तहत पूरा करना संभव नही होता है। यह समस्या हर सरकार के समय रहती है चाहे कांग्रेस हो या भाजपा। प्रदेश के युवाओं की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है और रोजगार का सबसे बड़ा साधन प्रदेश में सरकार से अतिरिक्त कोई नही है। सरकार में नौकरी पाने के लिये मैरिट से ज्यादा सिफारिश चाहिये यह धारणा आम बन चुकी है। प्रदेश के लोकसेवा आयोग से लकर अधीनस्थ सेवा चनय बोर्ड तक पर मैरिट को नजरअन्दाज किये जाने के आरोप लगते रहे है। सहकारी बैकों और परिवहन निगम की भर्तीयों को जो अदालत तक में चुनौतियां दी जा चुकी हैं। प्रदेश के औद्यौगिक क्षेत्र पर नौकरियों के लिये आश्रित रहना संभव नही है क्योंकि अब तक औद्यौगिक नीतियों के कारण ही प्रदेश भारी भरकम कर्जे के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। प्रदेश के मतदाता के सामने यह सबसे बड़ी समस्या है और इसके हल के लिये वह किसी भी दल पर भरोसा करने की स्थिति में नही है। इसलिये वह अब तक मौन चला हुआ है।

दूसरी ओर आज चुनाव प्रचार में कोई भी दल प्रदेश की इस बुनियादी समस्या पर बात नही कर रहा है। भाजपा का हर नेता प्रधानमन्त्री तक सरकार और वीरभद्र के भ्रष्टाचार को प्रदेश का मुख्य मुद्दा बनाकर प्रचारित कर रहा है। लेकिन इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आज तक प्रचार के अतिरिक्त और कोई कारवाई नही की गयी है। बल्कि वीरभद्र के मामले में केन्द्र की ईडी ने जिस तरह का आचरण अब तक बनाये रखा है उससे उसकी विश्वनीयता पर यह सवाल उठने शुरू हो गये हैं। वीरभद्र के भ्रष्टाचार पर जिस तरह से सारी भाजपा हमलावर हो रही है उससे यह सवाल भी चर्चा में आने लगा है कि वीरभद्र को बड़ी कारवाई से अब तक बचाता कौन आया है! इसके अतिरिक्त भाजपा से अब यह सवाल भी पूछा जाने लगा है कि जब उसने मोदी-शाह के चेहरों पर ही चुनाव लड़ने का फैसला अब तक प्रचारित रखा था तो उसे अचानक धूमल को चेहरा घोषित करने की आवश्यकता क्यों आ पड़ी? यदि भाजपा को अपनी नीतियों और उनकी जनस्वीकारयता पर भरोसा था तो उन्हे हिमाचल में भी कांग्रेस के अन्दर सेंघ लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? फिर कांग्रेस से भाजपा में गये हर व्यक्ति ने चाहे वह सुखराम और उनका परिवार हो या मुख्यमन्त्री वीरभद्र सिंह की पत्नी पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह की भाभी विजय ज्योति सेन या हिमाचल निर्माता और प्रदेश के पहले मुख्यमन्त्री डा. परमार के पौत्र हों सबने कांग्रेस छोड़ने का कारण व्यक्तिगत उपेक्षा होना बताया है। किसी ने भी यह नही कहा है कि उसे कांग्रेस की नीतियों पर एतराज है न ही यह कहा है कि वह भाजपा की विचारधारा से प्रभावित होकर यह कदम उठा रहा है। दलबदल के लिये केवल राजनीतिक स्वार्थ ही सबसे बड़ा कारण रहा है। भ्रष्टाचार के कारण ज़मानत पर होने के आरोप दोनों दलों के शीर्ष नेतृत्व पर एक बराबर हैं। फिर जिस तरह प्रधानमन्त्री ने प्रदेश को पांच दानवों से मुक्त करवाने को आहवान किया है उस भाषा को भी लोगों ने ज्यादा नही सराहा है।

इस परिदृश्य में धूमल के नेता घोषित किये जाने की राजनीतिक आवश्यकता थी और उसके अनुसार यह घोषणा हुई थी। लेकिन इस घोषणा के साथ ही धूमल के चयन को राजपूत विरादरी को खुश करने का प्रयास करार दे दिया गया। इसके लिये यह तर्क दिया गया कि प्रदेश में राजपूत 37% है और जातिय गणित में सबसे अधिक जन संख्या है जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में ब्राहमणों की जन संख्या 28 लाख 5 हजार 628 और राजपूतों की 24 लाख 16 हजार 986 है। लेकिन राजपूत एंगल दिये जाने से ब्राहमण सुमदाय में रोष की स्थिति पैदा होना स्वभाविक है। इस जातिय गणित का कुप्रभाव भाजपा को कांगड़ा में तो कांग्रेस को मण्डी में झेलना पड़ सकता है। धूमल के नेता घोषित होने के बाद जगत प्रकाश नड्डा को

संयोगवश कुछ चुनाव सभायें रद्द करनी पड़ी हैं। खराब मौसम के कारण केन्द्र के कई नेता पूर्व घोषित पत्रकार वार्ताओं को संबोधित नही कर पाये हैं लेकिन इसे भी राजनीति के चश्मे से ही देखा गया है। इसलिये धूमल के नेता घोषित होने से जो यह उम्मीद थी कि आम आदमी पूरी तरह खुलकर पार्टी के पक्ष में खड़ा हो जायेगा वैसा हुआ नही है।

दूसरी ओर कांग्रेस में जितना समय वीरभद्र और सुक्खु ने आपसी स्कोर सैटल करने में लगा दिया उससे पूरी पार्टी का जितना नुकसान हो गया है उसकी भरपायी हो पाना संभव नही है। क्योंकि जब भाजपा के स्टार प्रचारकों तक की सूची जारी हो गयी थी तब तक सुक्खु और वीरभद्र का झगड़ा सुलाझा ही नही था। यही तय नही हो पा रहा था कि वीरभद्र को चुनाव की कमान मिलेगी या नही। लेकिन जब वीरभद्र को कमान मिल गयी और चुनाव टिकटों को वितरण हुआ तो उसमें कई स्थानों पर वीरभद्र के समर्थको को टिकट नही मिल पाये। इन स्थानों पर वीरभद्र के कुछ समर्थक विद्रोही होकर चुनाव लड़ रहे हैं। इन विद्रोहीयों के चुनाव लड़ने से निश्चित रूप से पार्टी के अधिकृत उम्मीदवारों को नुकसान पहुंचेगा ही। यह विद्रोही सीधे वीरभद्र के नाम लग रहे हैं। इसके अतिरिक्त पार्टी का चुनाव प्रचार अभियान बहुत कमजोर चल रहा है। इस समस कांग्रेस का संगठन चुनाव प्रचार के नाम पर कहीं नजर नही आ रहा है। भाजपा के हमलों का जवाब देने वाला कांग्रेस के कार्यालय में कोई है ही नही। बल्की कांग्रेस के उपाध्यक्ष हर्ष महाजन जो स्वंय चुनाव नही लड़ रहे हैं वह भी न तो कांग्रस के कार्यलय में दिख रहे हैं और न ही प्रचार में। वह केवल मुख्यमन्त्री का ही चुनाव देख रहे हैं। इस समय कांग्रेस का सारा प्रचार पार्टी के केन्द्रिय कार्यालय द्वारा भेजे गये छोटे बड़े नेताओं द्वारा संचालित हो रहा है। प्रदेश नेताओं से वीरभद्र के अतिरिक्त और कोई फील्ड में दिख ही नही रहा है और वीरभद्र नेताओं से ज्यादा सेवानिवृत अधिकारियों पर आश्रित होकर चल रहे हैं। कल तक यह लोग प्रदेश सचिवालय में बैठकर उनकी सरकार चला रहे थे और आज हॉलीलाज में बैठकर चुनाव का संचालन कर रहे हैं। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि कांग्रेस कहां खड़ी है और उसका भविष्य क्या होने वाला है।

इस परिदृश्य में जहां संगठन और प्रचार के नाम पर कांग्रेस कहीं दिख नही रही और उसके मुकाबले में भाजपा बहुत आगे चल रही है। इसके बावजूद भी मतदाता अभी तक चुप चल रहा है। माना जा रहा है कि जहां प्रदेश की जनता वीरभद्र के कुशासन स दुःखी है वहीं पर भाजपा से भी पूरी तरह प्रसन्न नजर नही आ रही है। यह स्थिति अधिकांश में त्रिशंकु विधानसभा की संभावना मानी जाती है। लेकिन अब भाजपा ने धूमल को नेता घोषित करके स्थिति को संभालने का प्रयास किया है। उससे भाजपा को काम चलाऊ बहुमत मिलने की संभवना कुछ बनती जा रही है। वर्तमान स्थिति में यह लगता है कि कहीं सरकार बनाने के लिये निर्दलीयों की आवश्यकता पड़ सकती है।